SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

ubl f'k{kk uhfr 2020 vkj Hkkjr dh ;qok 'kfä% mPp f'k{kk d ifjçs{; e

_pk flag (Ph.D.), राजनीति विज्ञान विभाग,
जी एल ए कालेज, मेदिनीनगर, पलामू, झारखंड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
_pk flag (Ph.D.), राजनीति विज्ञान विभाग,
जी एल ए कालेज, मेदिनीनगर,
पलामू, झारखंड, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

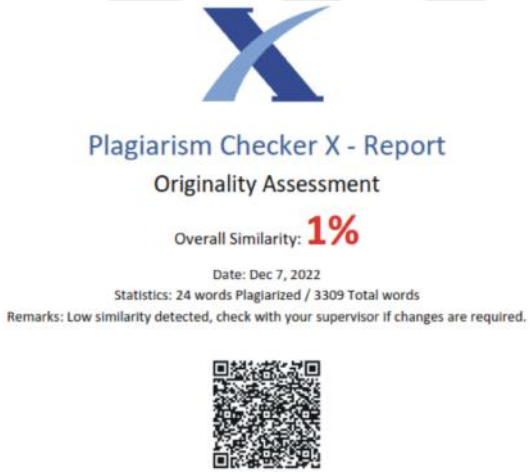

Received on : 07/12/2022
Revised on : -----
Accepted on : 15/12/2022
Plagiarism : 01% on 07/12/2022

Plagiarism Checker X - Report
Originality Assessment
Overall Similarity: **1%**
Date: Dec 7, 2022
Statistics: 24 words Plagiarized / 3309 Total words
Remarks: Low similarity detected, check with your supervisor if changes are required.

'kks/k lkj

नई शिक्षा नीति ने देश की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत बदलाव लाए हैं, जिनसे देश के युवा बेहतरीन शिक्षा हासिल करने के हकदार हो सकेंगे। पिछली शिक्षा नीतियों की कमियो को सुधारने की कोशिश भी इस नीति के मसौदे द्वारा की गई है। प्रस्तुत लेख में देश के युवक, युवतियां कैसे इस नीति से लाभांवित हो सकेंगे, इसी की चर्चा की गई है। देश के युवा वर्ग की शिक्षा पद्धति में बदलाव लाकर ही हम बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं क्योंकि वे ही देश की रीढ़ होते हैं। आजादी के बाद की जो भी कमियां रहीं उन्हें दूर करने की कोशिश शिक्षा नीति के विभिन्न नए आयामों द्वारा की गई है।

eq[; 'kCn

;qok] jkstxkj ijd] ekrHkk"kk] dk'ky fodkl] ubl f'k{kk uhfr-

एक सभ्य और श्रेष्ठ समाज की पहचान वहां शिक्षा के सभी स्तरों का सर्वांगीण विकास हैस इसी को हम किसी भी काल समाज राष्ट्र और वहां के नागरिकों के जीवन स्तर और मूल्यों को मापने का जरिया बना सकते हैं।

''डॉ. राम मनोहर लोहिया का कहना था ज्ञान और दर्शन से सब काम नहीं होता, ज्ञान और आदत दोनों को ही सुधारने से मनुष्य सुधरता है।'' [1] इसी परिप्रेक्ष्य में समझें तो नई शिक्षा नीति 2020 सार्थक और प्रासंगिक लगती है क्योंकि 1986 की शिक्षा नीति में शिक्षा व्यवस्था के प्रारूप को सुधारने की आवश्यकता थी साथ ही भारतीय समाज के ज्ञान के प्रति परंपरागत सोच को तोड़कर उसे व्यवहारोन्मुख, रोजगार परक और भारतीयता के तत्वों से परिपूर्ण करने की आवश्यकता थी। 1986 की पिछली शिक्षा नीति में बहु विषयक दृष्टिकोण, नवाचार,और वित्त पोषण एजेंसियों के बीच समन्वय का घोर अभाव था,

साथ ही शोध की व्यावहारिक समस्याओं के हल का जरिया खोजने की प्रवृत्ति पर बहुत कमजोर दिया गया था एनईपी 2020 ने स्वदेशी संस्कृति, भारतीय भाषाओं और अनुभव परक ज्ञान पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है।

भारतीय ज्ञान परंपरा जिसमें हम पाते हैं कि वैदिक काल से ही गुरुकुल व्यवस्थाएं थी जिनमें शाब्दिक ज्ञान के साथ–साथ व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता था यानी शिक्षा जीविकोपार्जन के साथ ही आत्ममंथन या सुधार का जरिया थी, जिससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो पाता था और ''विद्या या विमुक्तये'' की परिकल्पना साकार हो उठती थी। इन गुरुकुल केंद्रो से शारीरिक आध्यात्मिक, भौतिक, भावनात्मक और बौद्धिक रूप से पूर्ण विकसित युवा समाज का हिस्सा बनता था यानी हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए वह पूर्ण सक्षम होता था।

एन ई पी का उच्च शिक्षा संबंधी प्रस्ताव वह मसौदा है जो उच्च शिक्षा के जरिए भारत को पुनः वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाने की योजना हमारे सामने रखता है। नए सुधारों के बाद हमारी शिक्षा प्रणाली भारतीय लोकाचारों वाली होगी जो न केवल विचार में बल्कि आत्मा और बुद्धि से भी भारतीय होने का गहरा गर्व पैदा करेगी, साथ ही ऐसा मानवीय स्वभाव विकसित करने के संपूर्ण प्रयास होंगे जो बदलती दुनिया के प्रति भी युवा छात्र–छात्राओं को जिम्मेदार नागरिक बनाएंगे। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी प्रतिबद्ध युवा विकसित होंगे जो अपनी जिम्मेदारियों और भूमिकाओं के प्रति सतत जागरूक रहेंगे। वे न केवल अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, बल्कि अंतरर्राष्ट्रीय कानूनों और अवधारणाओं का भी सम्मान करेंगे। यह नीति युवाओं को उनकी रूचि के अनुसार बहु विषयक अध्ययन के विकल्प देगी। ज्ञान के सभी पहलुओं को अध्ययन का हिस्सा बना दिया गया है। युवक–युवतियां चाहे किसी भी अध्ययन क्षेत्र के हों, इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि स्वभाषा, स्वदेशी और नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हों, बौद्धिक जिज्ञासा विकसित करें और वैज्ञानिक सोच रखें साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 का स्वप्न युवाओं में उच्च शिक्षा के जरिए रचनात्मकता, कौशल विकास, सेवा की भावना और 21वीं सदी के अनुरूप तकनीकी गुणों से सक्षम पीढ़ी का निर्माण करना है। पश्चिम के विकसित देशों के समकक्ष खड़ा हो सकने के लिए आधुनिकतम शिक्षा माध्यमों को भी नई तकनीकों से लैस किया जाना आवश्यक है।[2] यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफ़ेसर धीरेंद्र पाल के अनुसार, जब पश्चिम के विकसित देशों में चौथी औद्योगिक क्रांति हो रही है जिस में सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिंटिंग ऑटोमेशन बिग डाटा पर काम हो रहा है तब सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा को जोड़ने का बड़ा कदम भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के जरिए उठाया गया है।

वस्तुत 21वीं सदी में बड़े पैमाने पर एक ऐसे समाज का वर्चस्व रहा है जो सूचना और ज्ञान से प्रेरित है। हमारे शिक्षा संस्थानों से यह उम्मीद की जाती है कि वह सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे क्योंकि हमारे युवा वर्ग को शिक्षित करने का दायित्व उन्हीं के ऊपर है, अर्थात् युवाओं का भविष्य वही गढ़ेंगे। चूंकि सर्वश्रेष्ठ ढंग से शिक्षित युवा ही बेहतरीन व्यवस्था बनाएंगे, दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सफल हो सकेंगे इसीलिए नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के स्तर पर आमूलचूल सुधार की योजना लोगों के समक्ष रखी गई है। ''उच्च शिक्षा सामाजिक आकांक्षाओ, विकास प्राथमिकताओं और सामाजिक मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण है।''

45000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली काफी विशाल है, जिसमें 2001 के बाद से 4 गुना वृद्धि देखी गई है। भारत की जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति से यह संकेत मिलता है यह आबादी के स्तर पर जल्द ही चीन से आगे निकल जाएगा।[3] हालांकि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया की वृहदतम प्रणालियों में से एक है लेकिन यह सीखने–सिखाने के बेहद औसत स्तर, बढ़ती सार्वजनिक निजी भागीदारी, छात्र–छात्राओं के विदेश में शिक्षा के प्रति रुझान और सम्मोहन, अनुसंधान के खराब स्तर, भूमंडलीकरण और अंतरर्राष्ट्रीयकरण और नव उदारवादी अर्थव्यवस्था की नई चुनौतियों जैसी असंख्य समस्याओं का सामना कर रही है।

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (आई एस एच ई) के अनुसार, 2019–20 मे भारत का सकल नामांकन अनुपात जी ई आर 27 प्रतिशत रहा जो वैश्विक औसत 36.7 प्रतिशत से काफी कम रहा। एनईपी 2020 का लक्ष्य 2035 तक 50 प्रतिशत करना है। मौजूदा समय में उच्च शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं ये हैः

- एक गंभीर रूप से तालमेल विहीन उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र।
- संज्ञानात्मक कौशल और प्राप्त ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग पर जोर न देने की प्रवृत्ति।
- विषयों का कठोर पृथक्करण।
- छात्रों के अध्ययन का क्षेत्र बेहद संकीर्ण होना।
- सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में उच्च शिक्षा की सीमित पहुंच।
- छात्र–छात्राओं और शिक्षकों का खराब अनुपात अर्थात् कम शिक्षकों की वजह से संस्थानों की गुणवत्ता पर गंभीर असर नजर आता है।
- संस्थागत स्वायत्तता की कमी।
- अधिकांश विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान पर कम जोर।
- शैक्षिक प्रशासको का कम प्रशिक्षित होना और नवाचारो की प्रवृत्ति से हिचकना।
- विश्वविद्यालयों पर बहुत ज्यादा कॉलेजों तकनीकी और व्यवसायिक संस्थानों को संभालने का बोझ।
- कम प्रभावी रेगुलेटरी एजेंसी या नियामक प्रणालियां।

नई शिक्षा नीति की परिकल्पना महत्वपूर्ण परिवर्तनों को लाने की है जिससे भारत के युवा वर्ग को अपनी मौलिक सोच विकसित करने, शिक्षा की बहुआयामी बहु विषयक पद्धति को आत्मसात करने, समाजोपयोगी शोध करने की दिशा में अग्रसर हो सकने के पर्याप्त मौके मिल सकेः

- अन्य भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना।
- बहु विषयक मल्टीडिसीप्लिनरी शिक्षा की ओर बढ़ना।
- संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की दिशा में कदम बढ़ाना।
- पाठ्यक्रम शिक्षा पद्धति मूल्यांकन प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव लाना और छात्रों के साथ ज्यादा संवाद, परामर्श और सहायता करना।
- संस्थाओं में शैक्षिक प्रशासकों की सत्य निष्ठा की पुष्टि करना।
- एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एन आर एफ) की स्थापना करना।
- शैक्षणिक और प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र बोर्डो द्वारा विश्वविद्यालयों को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता देना।
- सीमित लेकिन सख्त नियामक कानूनों की व्यवस्था करना ताकि संस्थानों की आजादी उच्च श्रृंखला में न बदल जाए।
- संस्थाओं और उसमें पढ़ने वाले युवाओं दोनों ही स्तरों पर नई शिक्षा नीति परंपरागत ढंग से चली आ रही।
- सीमित लेकिन सख्त नियामक कानूनों की व्यवस्था करना ताकि संस्थानों की आजादी उच्च श्रृंखला में ना बदल जाए।

एनईपी परंपरागत ढंग से चली आ रही ''रटंत शिक्षा'' और एकल स्ट्रीम वाली शिक्षा की जगह ज्ञान के दरवाजे छात्र–छात्राओं के लिए खोल देना चाहती है। कोई भी छात्र–छात्रा एक कोर्स को बीच में छोड़कर अपनी रुचि और विषय के दूसरे कोर्स में जा सकता है, जो चली आ रही शिक्षा पद्धति में संभव नहीं था। 1 साल में कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट और 2 साल में कोर्स छोड़ने पर डिप्लोमा जैसे अभिनव अनुप्रयोग युवा वर्ग को कुंठा से बचाएंगे क्योंकि उसके सामने मनपसंद शिक्षा के विकल्प हासिल करने के मौके उपलब्ध रहेंगे।

नई शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर 29 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं की आशा, आकांक्षाओं और भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हम कितना आगे जाएंगे कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में कैसी

शिक्षा और कैसी दिशा दे रहे हैं।[4] प्रधानमंत्री ने अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और विद्या प्रवेश सहित शुरू किए गए नए शैक्षणिक कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआईः कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के कार्यक्रम युवाओं को भविष्य मुखी बनाएंगे। यह सच है कि रोज बदलती हुई तकनीकों से भरी इस दुनिया में भविष्य की सभी कल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिए युवाओं को ही कदम बढ़ाने होंगे।

स्वास्थ्य, अनुसंधान, रक्षा, ढांचागत सुविधाओं, तकनीक, कृषि और उद्योग सब में आगे जाने के लिए देश को हर दिशा में समर्थ और आत्मनिर्भर होना होगा।

यह सच है कि देश की तकदीर युवा के हाथ में ही होती है। जयप्रकाश नारायण जैसे संघर्षशील नेता और विचारक ने युवा वर्ग को ही परिवर्तन का जरिया बताया था। कौटिल्य, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी आदि ने भी युवा वर्ग के कंधों पर ही देश की तकदीर होने का आह्वान किया था। जेपी के अनुसार उनके जरिए ही परंपरागत और गलत मान्यताओं पद्धतियों और व्यवहारों को बदला जा सकता है। युवा ही परिवर्तन के संवाहक होंगे।[5]

स्वतंत्रता के बाद का भारतीय परिदृश्य गवाह है कि युवा शक्ति ने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, भाषा, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर आंदोलन किया है और युवा असंतोष हमेशा शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रेरणा स्रोत बनता रहा है। पूर्ण रुप से लागू किए जाने पर एनईपी युवा वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और वे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय परिसरों में आंदोलन असंतोष और अनुशासन अनुशासन हीनता की जगह एक रचनात्मक और सुखद भविष्य बनाने के स्वप्न को साकार करने में लग जाएंगे।

आजादी के बाद से चली आ रही शिक्षा प्रणाली न तो युवा को पूर्ण स्वावलंबन दे रही थी न ही भारतीय संस्कार का बोध कराती रही है। ''लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई इस शिक्षा पद्धति से आज की युवा पीढ़ी अपने चिरंतन गौरव को भूलती जा रही है। हमारा राष्ट्रीय चरित्र दिनोंदिन क्षरित होता जा रहा था। एन ई पी में आधारभूत विषयों– शारीरिक शिक्षा, योग, नैतिक और मूल्यपरक शिक्षा, संगीत, संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं को प्रमुखता से जगह दी गई है।''[6]

वर्तमान भारत में 18 से 35 वर्ष की आयु वाले लगभग 42 करोड युवाओं की मानवीय पूंजी है पर उनमें से 70 प्रतिशत यानी लगभग 29 करोड गांवों में रहती है।[7] दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा के जरिए श्रेष्ठ संस्थानों के विशेषज्ञों के ज्ञान और अनुभव का लाभ ग्रामीण और कस्बाई इलाके के विद्यार्थी भी उठा सकते हैं बशर्ते उन्हें पर्याप्त तकनीकी साधन उपलब्ध कराए जाएं। ''आज हमारे देश में ग्रामीण युवा शक्ति के सामने अनेक गंभीर चुनौतियां हैं जिनमें सर्व प्रमुख मूल्य रहित और रोजगार विहीन शिक्षा ही है।'' इससे हर साल बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाती है। इस कारण कई बार युवा आपराधिक और आतंकवादी नक्सलवादी शक्तियों के चंगुल में भी आ जाते हैं।

शिक्षा नीति में कौशल विकास की व्यवस्था स्कूल स्तर से ही कर दी गई है और महाविद्यालय स्तर तक आते–आते हमारे युवाओं के हाथ ''हुनर विहीन'' नहीं रहेंगे। शिक्षा के पश्चिमी मॉडल, पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण ने हमारे युवाओं को कौशल रहित तो बनाया ही, मातृभाषा को हेय मानना भी सिखा दिया। इससे असंख्य प्रतिभाएं पीढ़ी दर पीढ़ी कुंठा का शिकार होती रही हैं क्योंकि वे अपनी भाषा में ही अपना सर्वोत्तम लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकती थी। गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में विदेशी भाषा में शिक्षण पद्धति को बढ़ावा देने के खतरे के प्रति आगाह किया था। उन्होंने कहा था, ''हमें समझना चाहिए कि अंग्रेजी शिक्षा लेकर हमने अपने राष्ट्र को गुलाम बनाया है। अंग्रेजी भाषा से दंभ, द्वेष और जुल्म वगैरह बढ़े हैं। यह क्या कम जुल्म की बात है कि अपने देश में अगर मुझे इंसाफ पाना हो तो मुझे अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना चाहिए। बैरिस्टर होने पर मैं स्वभाषा में बोल ही नहीं सकता। यह गुलामी की हद नहीं तो और क्या है। हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले तो हम अंग्रेजी जानने वाले लोग ही हैं।''[8]

पर हमने आजादी के बाद गांधीवादी विचारों की पूरी तरह अवहेलना की इसीलिए अपनाई गई शिक्षा पद्धति ने युवाओं को श्रम से दूर कर दिया। गांधीजी के मुख्य विचारों में से एक कायिक श्रम या ब्रेड लेबर की अवधारणा

है जिसका अर्थ है अपनी काया (शरीर) द्वारा नियमित रूप से श्रम करना। अपनी किताब हिंद स्वराज में उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि एक वकील या दूसरे प्रोफेशनल के काम का उतना ही महत्व है जितना एक मोची के काम का। हम भारतीयों में पढ़ाई के बाद बेरोजगार रह जाना बेहतर समझने और मेहनतकशों के काम को हेय समझने की मनोवृति बन गई। शिक्षा नीति कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा के साथ हुनर का तालमेल प्रस्तुत करती है ताकि महज डिग्री धारी बेरोजगारों की फौज आगे चलकर न खड़ी हो।

भारत ने हमेशा से युवा शक्ति को मुख्यधारा में रखा है और सम्मान दिया है, चाहे वह कौटिल्य द्वारा अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की राजगद्दी देकर अखंड भारत बनाने का सपना देखना हो या फिर विवेकानंद, रवींद्र नाथ टैगोर और जेपी जैसे नेताओं का युवाओं में अटूट विश्वास। नई शिक्षा नीति में भी बदलाव के केंद्र में युवा है। आमतौर पर हम प्राइमरी या सेकेंडरी स्तर के विद्यार्थियों का आंदोलन विरोध प्रदर्शन आदि नहीं देखते। विभिन्न मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर के युवा ही मुखर असंतोष प्रकट करते हैं। शिक्षा नीतियों में भी बदलाव को लेकर आंदोलन युवाओं ने ही किए हैं।

एनईपी 2020 शैक्षणिक सुधारों के जरिए भारत को ज्ञान का अद्वितीय केंद्र बना देने का लक्ष्य हमारे सामने रख रही है ताकि हम विदेशी विश्वविद्यालयों की समकक्ष श्रेणी में आ खड़े हों। इससे प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) तो रुकेगा ही, साथ ही विश्व भर की प्रतिभाएं भी पढ़ाई के लिए भारत की तरफ आकर्षित होंगी जैसा प्राचीन भारत में होता था।

शोध के क्षेत्र में प्रतिभाशाली युवाओं को बेहतरीन माहौल देने और शोध संस्कृति विकसित करने के लिए एन आर एफ यानी राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की योजना है। शिक्षा के क्षेत्र में अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी ज़ी डी पी का 6 प्रतिशत तक खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि भारत में ज्यादातर शोध औसत दर्जे का होता है, देशभर में उसका दोहराव भी होता रहता है। इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार के भी बहुत से मामले प्रकाश में आते हैं। इन सब पर अंकुश लगाने और उपयोगी शोध हासिल करने के लक्ष्य से एन आर एफ की स्थापना की गई है। इन सब लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यह आह्वान किया गया है कि पहले से मौजूद संस्थानो जैसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, विद्यालय अनुदान आयोग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग आदि के साथ मिलकर एनआर एफ काम करेगा। वह इन फंडिंग एजेंसियों के साथ नजदीकी समन्वय रखेगा ताकि शोध के दोहराव से बचा जा सके और नवाचार की संस्कृति बनाई जाए। शोधकर्ताओं और संबंधित सरकारी विभागों के साथ–साथ कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र आदि के बीच सेतु का काम करेगा ताकि शोधकर्ताओं को संबंधित क्षेत्र की जरूरतों की सूचना दी जा सके और कृषि, उद्योग जगत आदि को नए शोध और आविष्कारों की सूचना दी जा सके। यह सुधारात्मक कदम भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने में मदद करेगा क्योंकि अन्य देशों से नीतियों विचारों या प्रौद्योगिकी का आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षाविदों और युवा शोधकर्ताओं के लिए बेहद सकारात्मक कदम है। सरकार इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करेगी तो शोधकर्ता बेहतर अनुसंधान के माहौल में काम करेगा और नतीजे भी अच्छे आएंगे।

व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए कृषि विश्वविद्यालय, कानूनी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय और विभिन्न क्षेत्रों में स्टैंड अलोन विश्वविद्यालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और युवा उन्हें बेहतर विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। स्कूली स्तर पर ही कौशल विकास की योजना विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल करके की जाएगी। ''प्रायः ऐसा माना जाता है कि शुरुआती समग्र एवं जीवन पर्यंत कौशल विकास की मनोवृति का होना युवा वर्ग के लिए जरूरी है। इससे उनमें रोजगार प्राप्त करने की क्षमता, उद्यमशीलता और कार्य बल के साथ तालमेल बिठाने की प्रतिभा विकसित होगी। आदर्श रूप में नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों के अनुसार सामान्य शिक्षा का तात्पर्य आधारभूत एवं विभिन्न विधाओं में काम आने वाले कौशल का सामूहिक लक्ष्य हासिल करना है।''[9]

इसके अलावा यह नीति जेंडर इंक्लूजन फंड और पिछड़े तथा वंचित इलाकों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर दे रही है। इससे शहर और गांव के बीच शैक्षणिक विकास का जो अंतर है, वह दूर होगा। जिन गुणवत्तापूर्ण मानकों की चर्चा पूरे राष्ट्र में की गई है वे सही अर्थों में कार्यान्वित हो जाएं तो संपूर्ण भारत में शिक्षा का स्तर बेहतरीन हो जाएगा।

इसके अलावा शिक्षा के अंतरर्राष्ट्रीयकरण की भी बात की गई है। इस को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, सरकार और सभी उच्च शिक्षा निकायों को मिलकर काम करना चाहिए। विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में भारत की उच्च शिक्षा के लाभों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूतावासों को भी सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय और अन्य शीर्ष निकायों के साथ बातचीत से नीतियों और कानूनों को सरल बना कर भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के अध्ययन के प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। प्रयास हमें हर स्तर पर करने होंगे। इससे भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने में मदद मिलेगी।

लंबे विचार मंथन और बड़ी संख्या में परामर्श दाताओं के सुझावों को ध्यान में रखते हुए एन ईपी का मसौदा तैयार किया गया। परामर्शदाताओं में 200000 से ज्यादा लोग शामिल रहे हैं।

fu"d"k

हालांकि नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करने की चुनौती हम सबके सामने है। उम्मीद की जाती है कि जिस तरह से इसका स्वागत किया गया है वैसे ही विभिन्न स्तरों पर इसको लागू करने में भी शैक्षणिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सहयोग किया जाएगा। युवाओं सहित शिक्षा से जुड़े हर भारतीय के जीवन में यह सुखद बदलाव ला सकेगी। भारत का विश्व गुरु बनने का सपना भी तभी साकार हो सकेगा।

lanHkZ lwph

1. अच्छी khabar.com
2. धीरेंद्र पाल, दैनिक जागरण, 2 फरवरी, 2022 पृ सं 4।
3. शिक्षा नीति युवाओं के लिएः प्रधानमंत्री मोदी, दैनिक जागरण, 29 जुलाई 2021, पृ सं 1।
4. Outlook.com
5. विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद, द ड्रीम ऑफ ए रिवॉल्यूशन, पेंगुइन बुक्स 2021,पृ सं 103।
6. मोहन लाल सालवी, दैनिक भास्कर, 13 जनवरी 2015,पृ सं 4।
7. 'युवा शक्ति और ग्रामीण भारत' शिक्षा विमर्श, 12 नवंबर 2012, पृ सं 2।
8. मोहनदास करमचंद गांधी, हिंद स्वराज, 1909 (मूल प्रकाशन वर्ष) राजपाल प्रकाशन 2015,पृ सं 117।
9. केपी कृष्णन, बिजनेस स्टैंडर्ड, 6 अगस्त 2021।

****